

प्रकाशन का
107 वाँ वर्ष

अजय

3 रूपये मात्र



लखनऊ, गुरूवार 5 नवम्बर, 2026 | Online Edition : www.ajhindidaily.com | नगर संस्करण पृष्ठ-12 | मूल्य 3.00 रुपये

वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, (मध्य प्रदेश संस्करण), कानपुर, (झांसी संस्करण), लखनऊ , आगरा, बरेली, पटना, रांची, (धनबाद संस्करण) तथा जमशेदपुर से प्रकाशित

केन्द्र ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए 17,314 करोड़ की दो परियोजनायें को दी मंजूरी



लिथियम और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ की योजना

नयी दिल्ली (आससे.)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी। इनमें 92 जीडब्ल्यूएच ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए 14,500 करोड़ रुपये का व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण शामिल है। इसके अतिरिक्त, लिथियम और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु 2,814 करोड़ रुपये की योजना को भी हरी झंडी मिली।इन दोनों योजनाओं के लिए कुल 17,314 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। ऊर्जा भंडारण योजना वित्तीय वर्ष 2027 से वित्तीय वर्ष 2031 के बीच लागू होगी। यह भारत के 2030 तक 500 जी डब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।

अब सभी अग्निवीर परमानेंट सैनिक बन सकेंगे

सर्विस भी 4 से बढ़ाकर 6 साल; अभी तक 25 प्रतिशत को पक्की नौकरी, बाकी होते थे बाहर

नयी दिल्ली। अग्निवीर अब चार की बजाय छह साल तक सेना में नौकरी कर सकेंगे। पहले सिर्फ 25 प्रतिशत अग्निवीर सेना में स्थायी नौकरी पाते थे बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीर बाहर हो जाते थे। अब नये नियमों के तहत सेना इन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल देगी और उसके बाद स्थायी सैनिक बनने की पेशकश करेगी। इन 75 प्रतिशत सैनिकों को उनकी इच्छा तथा सेनाओं के चयन मानदंडों के आधार पर सेनाओं में स्थायी सैनिक बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय सेनाओं की सिफारिश पर लिया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना अपने मूल रूप में जारी रहेगी। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि यह निर्णय बहुत सोच विचार के बाद अग्निवीरों के प्रशिक्षण के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन, फिटनेस और अनुशासन को



देखते हुए लिया है और अब तक के सभी बैचों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को शुरू करते समय स्पष्ट किया गया था कि इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और यह निर्णय समीक्षा पर ही आधारित है। उन्होंने कहाकि इच्छुक 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए दो वर्ष के सेवा विस्तार की शुरूआत अग्निवीरों की आकांक्षाओं और संगठनात्मक दक्षता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के मूल उद्देश्य से, विचार-विमर्शपूर्ण, तर्कसंगत एवं विस्तृत मूल्यांकन तथा प्राप्त फीडबैक के बाद की गई है। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि अग्निपथ योजना 14 जून 2022 में शुरू की गयी थी और उसके मूल रूप में यह व्यवस्था थी कि अग्निवीरों का कार्यकाल चार वर्ष का रहेगा और चार वर्ष के बाद इनमें से केवल 25 प्रतिशत को मेरिट के आधार पर स्थायी सैनिक के तौर पर सेना में भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेनाओं की सिफारिश पर सरकार ने अग्निवीरों के अब तक के सभी बैचों के अग्निवीरों को नियमित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। चार वर्ष पूरे होने के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर स्थायी किया जायेगा जबकि बाकी बचे 75 प्रतिशत को दो वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो वर्ष के बाद 75 प्रतिशत में शामिल सभी अग्निवीरों को सेनाओं में स्थायी सैनिक बनने का मौका दिया जाएगा।श्री वैष्णव ने कहा कि सेनाओं और सरकार दोनों का यह मत है कि अग्निपथ योजना बेहद फायदेमंद रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में इससे पहले भी सुधार और उनकी समीक्षा की जाती रही है और सुधार तथा समीक्षा की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बताया कि फिलहाल तीनों सेनाओं में करीब 3.18 लाख अग्निवीर सेवा दे रहे हैं।

नशे में रहने वाला जनता को नशे से नहीं बचा सकता-राहुल

संगरूर में की जनसभा, मान सरकार पर बोला हमला



पंजाब (एजेंसी)। संगरूर के गांव फगुवाला में कांग्रेस की इंसाफ रैली में राहुल गांधी ने मान सरकार और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सबसे पहले मंच पर मौजूद दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता का जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज पंजाब में नशा और गैंग्सटरिज़्म सबसे बड़ा संकट बन चुका है। राहुल गांधी ने मूसेवाला के अपनी पुरानी मुलाकात को याद करते हुए कहा कि सिद्धू मूसेवाला बेहद टैलेंटेड और ऊर्जावान युवा थे। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि जिस सोच ने मूसेवाला को दिन-दहाड़े और बिना डरे गोलियों से भून दिया, वह दुखद है। राहुल ने कहा कि जिस पिता को अपने जवान बेटे की अर्थी देखनी पड़े, उससे बड़ा दर्द इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद सरेआम उनकी हत्या कर दी गई। पंजाब में नशे के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब वह पहले पंजाब आए थे और उन्होंने नशे की बात कही थी, तब विपक्ष के तमाम दलों बीजेपी और अकाली दल ने उनकी बात को नकारा था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक प्रदेश में उद्योग, फैक्ट्रियां और खेती-किसानी मजबूत नहीं होगी, तब तक नशा और गैंग्सटरिज़्म का खात्मा नहीं हो सकता। आप सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि चुनाव के समय उन्होंने वादा किया था कि वे पंजाब से नशा पूरी तरह मिटा देंगे। जनता ने उन पर भरोसा भी किया, लेकिन आज सवाल यह है कि सरकार ने प्रदेश के किस कोने से नशा खत्म किया है?

राज्य विधानसभाओं के लिए भी बने डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म-ओम बिरला

नयी दिल्ली (आससे)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य विधानमंडलों के लिए संसद की तर्ज पर डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों की निगरानी, उन पर कार्रवाई और रिपोर्टों के समयबद्ध निस्तारण में मदद मिलेगी। केंद्र और राज्यों को मिलकर लेखापरीक्षा एवं मूल्यांकन की मजबूत व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। बिरला बुधवार को तिरुवनंतपुरम में संसद और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की लोक लेखा समितियों के सभापतियों के दो दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से विधायी निगरानी में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, लेकिन इसे मानवीय विवेक का विकल्प नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन के प्रत्येक रुपये का उचित हिसाब होना चाहिए और उसका उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए। लोक लेखा समितियों को सरकारी खर्च की जांच के साथ यह भी देखना चाहिए कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है या नहीं। कैग की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना भी जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष ने समितियों के सदस्यों और अधिकारियों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा राज्यों की बेहतर कार्यप्रणालियों और तकनीकी नवाचारों को साझा करने पर जोर दिया। उन्होंने सम्मेलन में अंगीकृत 'केरलम संकल्प' को लोक लेखा समितियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। सम्मेलन में 27 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संसद की लोक लेखा समिति के सभापति केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सार्वजनिक धन के इस्तेमाल की प्रक्रिया जटिल होने के कारण लोक लेखा समितियों को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करना होगा।



ज्ञानेश कुमार पर 20 साल पुराने आरोप की विजिलेंस जांच होगी



नयी दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 20 साल पुराने रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच होगी। केरलम के गृहमंत्री रमेश चेन्नितला ने विजिलेंस को जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला सड़क निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़ा है। उस समय ज्ञानेश कुमार राज्य में प्रमुख सचिव थे। कोल्लम के ठेकेदार साजन का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद पेमेंट करने के बदले 2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। इस समय कांग्रेस की अगुवाई में पूरे देश में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ स्ट्रक्रमें गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन ने 140 में से 97 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया।

राहुल गांधी 'फुस्स राकेट', लांच होने वाले नहीं-मुख्यमंत्री

'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा कार्यक्रम में कार्यकर्ताओंको किया संबोधित



गोरखपुर (आससे.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस, सपा सहित पूरा इंडी गठबंधन भारत की विकास व आत्मनिर्भरता की यात्रा में लगातार रोड़े अटका रहा है। कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन दिल्ली में अराजकता पैदा कर लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है। राहुल गांधी फुस्स रॉकेट हैं, जिनका बारूद खत्म हो चुका है, सिर्फ धुआं बचा है। कांग्रेस चाहे जितनी बार उन्हें लॉन्च कर ले, अब वह लॉन्च नहीं होने वाले। सीएम योगी आज गोरखपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अगुवाई में निकाली गई 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा शुरू करने से पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने श्री नवीन का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षधरा में प्रथम आगमन पर भावपूर्ण स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन के दल अगर चुनाव जीतते हैं तो परिणाम उनका पुरुषार्थ होता है। और, यदि जनता उनके नकारेपन के कारण जवाब दे देती है, वे हार जाते हैं तो ईवीएम पर दोष थोपना उनकी प्रवृत्ति बन गई है। सीएम योगी ने कहा कि एसआईआर की कार्यवाही पहली बार देश में नहीं हुई है।

एसएससी-सीजीएल 2026 : जारी हुई उत्तर कुंजी

नयी दिल्ली (आससे.)। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 (सीजीएल टियर-1) की संभावित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग ने उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं (रिस्पॉन्स शीट) भी उपलब्ध करा दी हैं। उम्मीदवार अब अपने उत्तरों का मिलान संभावित उत्तर कुंजी से कर सकते हैं। आयोग ने 4 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी उत्तर पुस्तिका और संभावित उत्तर कुंजी देख सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा। आयोग ने संभावित उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय सीमा तय कर दी है। उम्मीदवार 4 नवंबर 2026 सुबह 9 बजे से 7 नवंबर 2026 रात 9 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

बीएचयू और नगर निगम वाराणसी को बमसे उड़ाने की मिली धमकी

ई मेल से मिली धमकी के बाद प्रशासन अलर्ट, भारी पुलिस बल के साथ की गयी सघन चेकिंग, दहशत का रहा माहौल

वाराणसी (का.प्र.)। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और नगर निगम को बुधवार को सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरा ई मेल मिलने से दहशत फैल गयी। इस सूचना पर वाराणसी पुलिस अलर्ट हो गयी। भारी संख्या में पुलिस फोर्स बीएचयू और नगर निगम पहुंची। परिसर को खाली करा दिया गया। जिससे अफरा-तफरी मच गयी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था एवं मुख्यालय) शिवहरी मीणा, डीसीपी काशी गौरव वंशवाल मौके पर पहुंचे थे। पूर्व में वाराणसी में आतंकवादी घटनाएं हो चुकी है। जिसको देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। घंटों चली जांच पड़ताल में किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार वाराणसी नगर निगम और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को आतंकवादियों के द्वारा मिले धमकी भरे ई मेल से जिला प्रशासन में हड़कम्प मच गया। बुधवार की अल सुबह नगर निगम वाराणसी को मिले ई-मेल पर लिखा था। महापौर और नगर निगम को बम से उड़ा दिया जायेगा। इसकी सूचना नगर निगम के अफसरों ने जिलाधिकारी और वाराणसी पुलिस कमिश्नर को तत्काल दी गयी। इस सूचना पर एसीपी चेतगंज शुभम सिंह तथा सिगरा थाना प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्र बम निरोधक दस्ता और क्यूआरटी टीम के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे और परिसर को खाली कराया गया।

पंजाब : आप विधायक के सात ठिकानों पर ईडी का छापा

चंडीगढ़ (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पंजाब में एक साथ सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई मोगा जिले में सरकारी और संस्थागत संपत्तियों के कथित धोखाधड़ी से अधिग्रहण तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़े मामले में की गई है। ध्यान देने वाली बात है कि अमनदीप कौर मोगा से मौजूदा विधायक हैं और आम आदमी पार्टी ने 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी अपना उम्मीदवार चुना है। तलाशी के दायरे में आम आदमी पार्टी की महिला विंग की पंजाब प्रधान और मोगा की विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा, उनके पति डॉ. राकेश अरोड़ा, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े अन्य लोगों के परिसर शामिल हैं।

अमूल ने बढ़ाये घी-बटर के दाम

घी में 50 रुपये-बटर में 30 रुपये किलो की बढ़ोतरी

नयी दिल्ली (आससे.)। अमूल ने घी और बटर 3 से 50 रुपए तक महंगा कर दिया है। एक किलो घी का



कार्टन 630 से बढ़कर 680 रुपए का हो गया है। बटर के 100 ग्राम पैक की कीमत 63 से बढ़कर 66 रुपए हो गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, दाम बढ़ने की वजह गुजरात-राजस्थान में नकली घी के खिलाफ कार्रवाई के बाद ब्रांडेड घी की बढ़ी मांग है। इससे सितंबर 2025 की कटौती का फायदा भी काफी कम हो गया है। सितंबर 2025 में जीएसटी की दर घटने के बाद अमूल ने 700 डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम कम किए थे। डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया था। उस समय एक लीटर घी के कार्टन की कीमत 650 से घटकर 610 हो गई थी। पांच लीटर का टिन 3,275 से घटकर रु 3,075 हो गया था। बटर के 100 ग्राम पैक की कीमत 62 से घटकर 58 हो गई थी। 500 ग्राम पैक 305 से घटकर 285 का हुआ था। गुजरात में अमूल काउ घी की कमी दाम बढ़ने के साथ लोगों को अमूल के कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स मिलने में भी दिक्कत हो रही है।

दो से अधिक बच्चों पर चुनावी पाबंदी की प्रासंगिकता खत्म- सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली (आससे)। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए दो से अधिक बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने वाले कानूनों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया है। अदालत ने कहा कि देश में घटती प्रजनन दर और बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति को देखते हुए ऐसे कानूनों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि वर्ष 2003 में भारत की कुल प्रजनन दर तीन थी, जो अब घटकर 1.9 रह गई है। यह 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से भी कम है। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाए गए इन कानूनों का औचित्य अब समाप्त होता दिखाई दे रहा है।

अमेरिका : मिडटर्म चुनाव में ट्रंप की जबरदस्त हार

डेमोक्रेट्स पार्टी ने सीनेट-हाउस ने हासिल किया बहुमत



वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मतदाताओं से अपील की थी कि वे 2026 के मिडटर्म चुनावों को सीधे उनके कार्यकाल पर जनमत संग्रह समझकर मतदान करें।बुधवार को आए चुनावी नतीजों से साफ हो गया है कि जनता ने उनके इस आह्वान पर अपना कड़ा फैसला सुना दिया है। पूरे अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की जबरदस्त ब्लू वेव देखने को मिली, जिसके चलते डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों-हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है।यह परिणाम सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। डेमोक्रेट्स ने न केवल अपनी सीटें बचाईं बल्कि टेक्सास, कंसास, साउथ कैरोलिना और आयोवा जैसे दशकों पुराने रिपब्लिकन गढ़ों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की।





भारतीय जहाजों को ईरान ने दी होर्मुज से जाने की छूट

चीन समेत कई देशों को भी राहत



तेहरान (एजेंसी)। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। ईरान सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भारतीय जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से आने-जाने की छूट दी गई है। ईरान ने भारत के अलावा चीन, इराक और कतर के जहाजों को भी अपने प्रतिबंधों से बाहर रखा है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के उपाध्यक्ष अहमद हयात-मोगद्दम ने कहा कि इन चार देशों के जहाज बिना किसी रोक-टोक के इस समुद्री रास्ते से गुजर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को यह छूट दवाइयों के आयात को ध्यान में रखकर दी गई है। वहीं, चीन को यह सुविधा राजनीतिक समर्थन के बदले दी गई है। इस बीच ईरान के भीतर अमेरिका के साथ फिर से युद्ध शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत कई बड़े नेता कतर की मध्यस्थता से बातचीत का रास्ता अपनाने के पक्ष में हैं। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के उपाध्यक्ष अहमद हयात-मोगद्दम ने कहा कि भारत, चीन, इराक और कतर को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की विशेष अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि इन देशों के जहाज ईरान की तरफ से स्वतंत्र हैं और इस समुद्री रास्ते से आ-जा सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका को भी इन देशों के जहाजों की आवाजाही से कोई समस्या नहीं है। हयात-मोगद्दम ने कहा कि भारत को यह छूट इसलिए दी गई है, ताकि वह दवाइयों का आयात कर सके।